Title: Alleged financial irregularities in the implementation of "National Rural Health Mission".

भी अर्जुन राम मेघवात (बीकानेर): सभापित महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया हैं। हमारे देश में राष्ट्रीय गूमीण स्वास्थ्य मिशन, एनआरएचएम एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही हैं। हमने अस्ववारों में पढ़ा कि उत्तर पूदेश में 3700 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ और बीस आदमियों का एक दल वहां गया। उसने पाया कि 250 करोड़ रुपए किसी विभाग में जमा थे, वे आने ट्रंसफर नहीं हुए। एम्बुलेंस समय पर नहीं खरीदे गए, टेंडर पूक्रिया प्रेपर नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूं कि जो एनआरएचएम स्किम हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट प्रोगूम मैनेजर, एकाउंट मैनेजर, एकाउंटेंट, डाटा एंट्री ओपरेटर, जीएनएम, एएनएम, फार्मिसिस्ट, लैब टैंवनीशियन, आशा सुपरवाइजर, कम्पांडर और आशा कार्डिनेटर आदि इतने पद होते हैं। मैं आपके ध्यान में ताना चाहता हूं कि ये सभी पद कांट्रेक्ट पर हैं। जब ये पद कांट्रेक्ट पर रहेंगे और स्थायी नहीं होंगे, तो इसी पूकार के घोटाले देश में और उजागर होंगे। मैं राजस्थान से आता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां 745 एकाउंटेंट थे, उनको भारत सरकार ने कह दिया कि एकाउंटेंट की जरूरत नहीं हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि आपने इन एकाउंटेंट्स को हटा दिया, आफिसर्स हटा दिया, तो जिस पूकार से यूपी में घोटाला हुआ है, उसी पूकार से दूसरे पूक्रिया को ते कर हैं। जो पैसा है, वह कहां है, कहां खर्च हुआ, यह पता नहीं तग रहा हैं। एकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं। मेरा सुझाव है कि इसमें तीन सुधार करने की जरूरत हैं। डाक्टर, स्टाफ और एकाउंटेंट ये संविदा पर नहीं होने चाहिए। एनआरएचएम बहुत बड़ी स्किम से कम इनके साथ दस साल का कांद्रेक्ट किरए। हर साल जो आप 6 महीने का कांद्रेक्ट करते हैं, यह क्या है? यह हमारी समझ में नहीं आता।

मेरा दूसरा सुझाव है कि इसी योजना में एक प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटेशन प्लान होता है और वह प्लान जब मर्जी आए, ये लोग बदल देते हैं। ये लोग कहते हैं कि अभी आपको 300 डॉक्टर की जरुरत हैं। जब आपने साल भर का प्लान लिया तो आप बीच में क्यों बदल रहे हैं? यह जो यू.पी. में घोटाला हुआ, यह इसी के कारण हुआ।

दूसरे, ये सारी अनियमितताएं वित्तीय क्षेत्र में हुई हैं। मेरा कहना है कि इनका जो एकाउंट विंग हैं, इसको सुद्ध किया जाना चाहिए नहीं तो अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में पीआईएल लगाई गई हैं, ...(<u>व्यवधान</u>) इसितए मेरा कहना है कि जो मैंने सुझाव दिये हैं, उनको इम्पलीमेंट किया जाए और इनके स्टॉफ को परमानेंट किया जाए, यही मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग हैं।